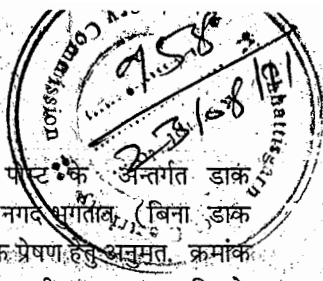


“बिजनेस पोस्ट” के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान, (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 जून 2011—ज्येष्ठ 11, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग  
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2011

क्रमांक 37/सी.एस.ई.आर.सी./2011.—विद्युत अधिनियम 2003, (वर्ष 2003 का क्र. 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा ऐसी अन्य शक्तियों, जो आयोग को इस हेतु समर्थ करती हो, का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विनियमों के पूर्व प्रकाशन के उपरांत एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ

- 1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन की संवीक्षा) विनियम 2011 के नाम से जाने जावेंगे.
- 1.2 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे.
- 1.3 ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे.

परिभाषार्थ एवं व्याख्याएं

- 2.1 संदर्भ से जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में—
  - (ए) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्र. 36)
  - (बी) “विनियमित निकाय” से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी, विद्युत व्यापारी और राज्य भार प्रेषण केंद्र.
- 2.2 उन अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनका प्रयोग इन विनियमों में किया गया है परंतु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थ वही होगा जो अधिनियम के अधीन उनका अर्थ है.

## 6. कार्य करने की विधि

- 6.1 आयोग द्वारा, ऐसा करने के निर्देश दिये जाने पर सलाहकार/अंकेक्षक किसी भी समय अपने एक या अधिक अधिकारियों के माध्यम से किसी विनियमित निकाय और उस निकाय द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों, बहियों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करेगा और उन निकायों के कार्यों की जांच ऐसी रीति से करेगा, जिसे आयोग उपयुक्त माने।  
परंतु, उस विनियमित निकाय को लिखित में ऐसे निरीक्षण और/या जांच की, सुविधायुक्त पूर्व सूचना दी जावेगी।
- 6.2 यह प्रत्येक विनियमित निकाय का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी लेखा पुस्तकों, बहियों और अन्य दस्तावेजों को, सलाहकारों/अंकेक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करे और उसे विनियमित निकाय के कियोकलापों से संबंधित उस वक्तव्य और सूचना के साथ प्रदान करे, जैसाकि उस सलाहकार/अंकेक्षक द्वारा अपेक्षित किया जावे, ऐसी जानकारी या सूचना सलाहकार/अंकेक्षक द्वारा लिखित में बताई गई समयावधि के भीतर प्रदान की जावेगी।
- 6.3 सलाहकार/अंकेक्षक, निर्वहित कार्यों और निष्कर्ष निकालने के लिए आधार के रूप में उपयोग करने हेतु पर्याप्त मात्रा में दस्तावेजी साक्ष्य संग्रहीत करेगा, एकत्र सूचनाएं सामान्यतः आद्योपान्त होंगी।
- a) आंकड़ों की मांग:- संबंधित विनियमित निकाय से आंकड़ों की मांग ही आंकड़े प्राप्त करने की प्रारंभिक विधि होगी। इस प्रकार अभिप्राप्त किये जाने वाले आंकड़ों में विस्तीय तथा संचालन संबंधी सूचना, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका संगठन-सारणी प्रतिवेदन, मुद्रित ई-मेल और वॉयस-मेल एवं अध्ययन सम्मिलित है। आवश्यकता के अनुरूप अभिप्राप्त किये जाने वाले आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक अथवा कागजी स्वरूप के हो सकते हैं।
- b) स्थल निरीक्षण:- संबंधित विनियमित निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समुचित अर्थान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सलाहकार/अंकेक्षक स्थल निरीक्षण करेगा। सलाहकार/अंकेक्षक संवीक्षा से सुसंगत होने पर अन्य बातों के अलावा कार्य स्थल से सामग्री एकत्र करेगा, प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा और आमने-सामने साक्षात्कार संचालित करने के अवसर उपलब्ध करायेगा।
- c) साक्षात्कार:- सलाहकार/अंकेक्षक व्यक्तिगत अथवा दूरभाष पर साक्षात्कार संचालित कर सकेगा, जैसे ही विनियमित निकाय से संवीक्षा के अधीन आंकड़ों का संग्रहण कर लिया जाए सलाहकार/अंकेक्षक उन्हें संकलित विश्लेषित करेगा। सलाहकार/अंकेक्षक/समूह विनियमित निकाय द्वारा आयोग के समक्ष तथा अन्य लोक अभिलेखों में पूर्व में प्रस्तुत जानकारियों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी संसूचनाओं का विश्लेषण करेगा। मिश्रित विस्तार पत्रक तथा आंकड़ों का आधार तैयार करने हेतु पूर्व विश्लेषण की आवश्यकता होगी और नमूनों का उपयोग अधिनियम, नियमों, विनिर्मित विनियमों, तथा आयोग द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों के परोक्ष अपालन के परीक्षण हेतु किया जाएगा।
- e) तीसरे पक्ष की शिकायतें:- तीसरे पक्षकारों द्वारा की गई शिकायतों के द्वारा भी अपालन का दायरा ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्राहकों की शिकायतें।
- 6.4 सलाहकारों/अंकेक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे आयोग को संपूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध करावें जिसमें कम से कम निम्नलिखित जानकारियों का समावेश हो:-
- a) प्रतिवेदन का दायरा और उसे तैयार करने की विधि, जिसमें निर्देश की शर्तों में विनिर्दिष्ट सभी विषय सम्मिलित हो, का विवरण;
- b) उन प्रणालियों एवं प्रक्रिया का विवरण जो विनियामक दायित्वों का परिपालन करते हुए स्थापित हुई हो, और जिसमें सुसंगत दस्तावेजीकरण उत्तरदायी स्थितियों की पहचान भी सम्मिलित है
- c) उत्पादन संबंधी अनुपालन के विषयों और उस प्रतिवेदन हेतु विशेष रूप से चिन्हित मुद्दों को संबोधित करते हुए इस आशय का विस्तृत विवरण कि किस तरह अनुपालन का प्रबंध किया जावे;
- d) चिन्हित अपालन और विनियमित निकाय द्वारा उसे दूर करने के संबंध में उठाये गये कदमों का विस्तृत विवरण और उन कदमों की पर्याप्तता का मूल्यांकन।
- 6.5 सलाहकार/अंकेक्षक/समूह द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन में निम्नलिखित कथन सम्मिलित होने चाहिए:-
- a) सलाहकार/अंकेक्षक/समूह द्वारा प्रतिवेदन तैयार करते समय तथा निष्कर्ष निकालते समय निर्देश की शर्तों के अनुपालन किये जाने संबंधी घोषणा;

- b) प्रतिवेदन में सलाहकार/अंकेक्षक का व्यवसायिक अभिमत प्रतिबिम्बित होना चाहिए;
- 6.6 सलाहकार/अंकेक्षक अपने प्रतिवेदन की एक प्रति विनियमित निकाय को भी प्रदान करेगा.
7. इन विनियमों के अधीन, प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आयोग, विनियमित निकाय को, ऐसा अभ्यावेदन, जो उसकी दृष्टि में तर्कसंगत हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, लिखित में आदेश देगा जिसमें, प्रतिवेदन में उल्लेखित अपालन या उल्लंघन, जैसी भी स्थिति हो, पाये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही का विवरण भी शामिल हो.
8. **कठिनाई दूर करने की शक्ति**  
यदि, इन विनियमों के किसी प्रावधान को प्रभावी बनाने में, कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपयुक्त कदम उठायेगा, जो अधिनियम से विसंगत न हो और, जिन्हें आयोग कठिनाईयां दूर करने के लिए आवश्यक, अथवा समुचित माने.
9. **संशोधन की शक्ति**  
आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकेगा.
10. अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन, आयोग, समय-समय पर इन विनियमों के प्रवर्तन के संबंध में आदेश, और प्रयोग संबंधी निर्देश, जारी कर सकेगा.

**नोट:** इस विनियम के हिंदी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

Raipur, the 1st June 2011

No. 37/CSERC/2011.— In exercise of powers conferred by section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:-

**1. SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT**

- 1.1 These regulations may be called "Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Compliance Audit) Regulations, 2011."
- 1.2 These regulations shall be applicable in the State of Chhattisgarh
- 1.3 These regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

**2. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS**

- 2.1 In these regulations, unless the context otherwise requires:
- (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) "Regulated Entities" mean distribution licensees, generation companies, transmission licensees, Electricity Traders, and State Load Dispatch Centres;
- 2.2 Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

**3. COMPLIANCE AUDITS**

- 3.1 The Commission may, at any time, conduct audits of regulated entities for verifying their compliance with the Act, rules, regulations made thereunder, orders and directions issued by the Commission.

- 3.2 The Commission, may, by order, empanel consultants / auditors / group of officers of the Commission (group) required to assist the Commission in the discharge of these functions on the terms and conditions as deemed fit.
- 3.3 The Commission may either appoint consultants / auditors/ group empanelled with it for an audit or go through the process of fresh selection, if required for a specific need.
- 3.4 The Commission may also consider the single source selection of consultants / auditors in exceptional cases where it is felt appropriate.
- 3.5 The Commission before initiating an audit will frame the terms of reference which will detail out the specific outputs that are to be provided by the Consultant / Auditor / group in relation to the task, the time frame in which the task has to be completed and other points relevant to the task.
- 3.6 The Commission shall assign, through an order, the specific task of audit to the consultant / auditor / group based on the terms of reference framed by it before the audit of the regulated entity starts.

#### 4 REQUIREMENTS OF CONSULTANT / AUDITOR

Consultants / auditors shall provide professional, objective, and impartial advice and at all times hold the Commission's interests regarding verification of compliance with the Act, Rules, Regulations made there under orders and direction issued by the Commission, without any consideration for future work, and that in providing advice they avoid conflicts with other assignments and their work corporate interests. Consultants / auditors shall not be hired for any assignment that would be in conflict with their prior or current obligations to other clients, or that may place them in a position of being unable to carry out the assignment in the best interest of the Commission. Without limitation on the generality of the foregoing, Consultants / auditors shall be engaged keeping in view the circumstances set forth below:

- (i) A consultant or an auditor engaged for a particular audit must not hold office or have a commercial or any other interest in the regulated entity for a period of Two (2) years preceding the engagement by the Commission.
- (ii) While conducting an audit, the consultant or auditor would be expected to do so honestly, fairly, professionally, independently objectively and exercise a standard of skill, care and diligence that would be reasonable to expect of a person who is skilled, and who has substantial experience, in the provision of services the same or as similar to those to be provided by the auditor.
- (iii) The selected consultant or auditor would be required to provide a written declaration to the Commission that he has no conflict of interest while performing the tasks and functions assigned to him under these regulations nor by its nature, may be in conflict with another assignment of the consultant or auditor.

#### 5 EXPENSES

- (i) All expenses of and incidental to, any audit made under these regulations shall be paid by the Commission and thereafter such expenses shall be defrayed by the regulated entity in favour of the Commission.
- (ii) The regulated entity shall be permitted to claim the said expenses as follows-
  - (a) Distribution licensees or transmission licensees may claim the said expenses as pass through in annual revenue requirement;
  - (b) Generation companies may claim the said expenses while filing application for determination of tariff.
  - (c) Electricity Traders may claim the said expenses as increase in trading margin with the approval of Commission.
  - (d) State Load Despatch Centre may claim the said expenses as pass through in its annual budget approval.

**6 METHODOLOGY**

6.1 The consultant / auditor may, at any time, and shall, on being directed so to do by the Commission, cause an inspection to be made, by one or more of his officers, of any regulated entity and his books of account, records and other documents in its custody, and to investigate into the affairs of the regulated entity in a manner as deemed fit by the Commission.

Provided that the regulated entity shall be given a reasonable advance notice in writing of such inspection and / or investigation.

6.2 It shall be the duty of every regulated entity, to produce before the consultant / auditor, all such books of account, registers, and other documents and to furnish him with any statement and information relating to the affairs of the regulated entity, as the said consultant / auditor may require of him within such time as the said consultant / auditor may intimate in writing in this behalf.

6.3 The consultant / auditor shall collect sufficient amount of evidence to document the work performed and to serve as the basis for the conclusions reached during the course of the audit. The information gathered will be generally through

a. Data Requests- The primary method of obtaining data shall be through data requests to the concerned regulated entity. The data obtained through data requests could include financial and operational information, procedure manuals, organization charts, reports, email and voice mail records, and studies. The data may be obtained either electronically or as paper documents (depending upon the requirement).

b. Site visits – The consultant / auditor shall conduct site visits to ensure accurate interpretation of the information provided by the concerned regulated entity. The consultant / auditor shall inter alia collect materials on site, observe processes, and offer an opportunity to conduct face to face interviews, as relevant to the audit.

c. Interviews – The consultant / auditor may conduct interviews in person and over the phone.

d. As the data are collected from the regulated entity under audit, the consultant / auditor shall compile and analyze the data. The consultant / auditor / group shall analyze information gathered from multiple sources, including earlier filings made before the Commission by such regulated entity, as well as from public records. Advance analysis may require the creation of complex spreadsheets and database, and the use of sampling to test for potential non-compliance of the Act, rules, regulations made thereunder, orders and directions issued by the Commission.

e. Third party complaints – Areas of non-compliance may also be identified through third party complaints, for example, customer complaints.

6.4 The consultant / auditor will be required to provide full reports to the Commission, which shall contain, as a minimum;

a) a description of the reporting scope and methodology, which should include all matters specified in the terms of reference;

b) a description of the systems and procedures that have been established to comply with regulatory obligations, including the identification of relevant documentation and responsible positions.

c) a discussion of how compliance is managed, addressing generic compliance issues and any specific issues identified for that report;

d) details of any non-compliance identified and the actions being undertaken by the regulated entity to rectify them, and an assessment of the adequacy of the actions.

6.5 The report shall include a statement, signed by the consultant / auditor / group which states that:

a) the term of reference have been complied with by the consultant / auditor / group in making findings and in preparing the report; and

b) the report reflects the professional opinion of the consultant auditor.

6.6 The consultant / auditor shall supply to the regulated entity a copy of his report.

7. On receipt of any report under these regulations, the Commission may, after giving such opportunity to the regulated entity, to make a representation in connection with the report as in the opinion of the Commission, seems reasonable, by order in writing take appropriate action under the Act on being satisfied regarding the non-compliance or contravention, as the case may be.

**8. POWER TO REMOVE DIFFICULTIES**

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

**9. POWER TO AMEND**

The Commission may at any time, amend any provisions of these regulations.

**10. ORDERS AND PRACTICE DIRECTIONS**

Subject to the provisions of the Act, the Commission may from time to time issue orders, and practice directions in regard to the implementation of these Regulations.

आयोग के आदेशानुसार,  
एन. के. रूपवानी, सचिव